

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 786
उत्तर देने की तारीख : 24.07.2025

सार्वजनिक खरीद नीति

786. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से वस्तुओं की खरीद हेतु नीतिगत दिशानिर्देश क्या हैं;
- (ख) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से की गई ऐसी खरीद का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में वर्तमान में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या कितनी है और छत्तीसगढ़ राज्य सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उद्यमों की सूची क्या है;
- (घ) क्या इस नीति के अंतर्गत खरीद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कोई दिशानिर्देश या अनुदेश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इस नीति के संबंध में एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 23 मार्च, 2012 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.आ. 581(अ), के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, आदेश, 2012 को अधिसूचित किया है। यह नीति (वर्ष 2018 में संशोधित) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से 25% वार्षिक खरीद अनिवार्य करती है, जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% शामिल हैं। इस नीति के अनुसार, एमएसई को निविदा सेट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे और उन्हें बयाना राशि जमा करने से छूट दी जाती है। नीति के अनुसार, कुल 358 वस्तुएँ खरीद हेतु आरक्षित हैं और उन्हें केवल एमएसई से ही प्राप्त किया जाना है।

(ख) : एमएसएमई संबंध पोर्टल के अनुसार सीपीएसई द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान एमएसई से की गई खरीद का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(ग) : देश में उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) पर वर्तमान में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 6,58,33,368 है (दिनांक 15.07.2025 तक)। एमएसएमई का छत्तीसगढ़ राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है।

(घ) : एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसयू पर लागू है। यह नीति राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू पर लागू नहीं है। देश भर में एमएसई के हितों को बढ़ावा देने हेतु मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को पत्र भेजे गए हैं जिनमें संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में इस नीति के कार्यान्वयन हेतु सहयोग का अनुरोध किया गया है। 26 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्र ने अपनी नीतियों को मंत्रालयों की नीति के अनुरूप बना लिया है।

(ड.) : सरकार ने उद्यमों में जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय किए हैं। यूआरपी के माध्यम से, कोई भी एमएसएमई जेम प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है और सरकारी खरीद में भाग ले सकता है।

एमएसएमई मंत्रालय की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की क्षमता वृद्धि करना है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना और सार्वजनिक खरीद नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों से खरीद के 4% अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करना है। इसके विभिन्न घटकों में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और जागरूकता शामिल हैं।

एमएसएमई मंत्रालय की खरीद एवं विपणन सहायता योजना के अंतर्गत, उद्यमों में जागरूकता पैदा करने के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा भी नियमित विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 786, जिसका उत्तर दिनांक 24.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

पिछले 5 वर्षों में सीपीएसई द्वारा एमएसई से वर्ष-वार वार्षिक खरीद

वित्त वर्ष	कुल खरीद (करोड़ रुपए में)	एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से खरीद (करोड़ रुपए में)	महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से खरीद (करोड़ रुपये में)
2020-21 (161 सीपीएसई)	1,39,419.81	40,717.67 (29.21%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-1,77,594)	768.53 (0.55%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-6,870)	749.20 (0.54%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-5,140)
2021-22 (162 सीपीएसई)	1,65,383.04	53,778.58 (32.52%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-2,27,049)	1,302.50 (0.79%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-10,437)	1,713.27 (1.04%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-11,383)
2022-23 (166 सीपीएसई 2 विभाग)	1,74,316.32	64,721.65 (37.13%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-2,36,433)	1,546.91 (0.89%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-10,354)	2,318.99 (1.33%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-16,725)
2023-24 (153 सीपीएसई और 1 विभाग)	1,70,985.96	74,727.12 (43.70%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-2,58,449)	1,761.78 (1.03%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-11,571)	3,154.97 (1.85%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-21,339)
2024-25 (149 सीपीएसई (दिनांक 22.07.2025 तक)	2,68,653.93	93,911.23 (34.96%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-2,92,733)	3,576.08 (1.33%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-21,404)	5,949.08 (2.21%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-33,703)

स्रोत: एमएसएमई संबंध पोर्टल

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 786, जिसका उत्तर दिनांक 24.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- II

दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 15/07/2025 तक उद्यम और यूएपी पर राज्य-वार कुल पंजीकृत उद्यम					
क्र. सं.	राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19261	157	3	19421
2	आंध्र प्रदेश	3360676	16491	942	3378109
3	अरुणाचल प्रदेश	39037	344	19	39400
4	असम	1183889	6523	519	1190931
5	बिहार	3573259	11635	560	3585454
6	चंडीगढ़	68200	1247	124	69571
7	छत्तीसगढ़	1135360	8198	701	1144259
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	29903	901	132	30936
9	दिल्ली	1191761	27734	2689	1222184
10	गोवा	112106	1094	79	113279
11	गुजरात	3699208	53058	4124	3756390
12	हरियाणा	1669870	22580	1729	1694179
13	हिमाचल प्रदेश	291899	2507	208	294614
14	जम्मू और कश्मीर	736820	3162	203	740185
15	झारखंड	1317404	5758	349	1323511
16	कर्नाटक	4332188	30775	2238	4365201
17	केरल	1576019	12627	744	1589390
18	लद्दाख	18480	112	2	18594
19	लक्षद्वीप	2208	0	0	2208
20	मध्य प्रदेश	4133259	19307	1150	4153716
21	महाराष्ट्र	8551716	72793	6694	8631203
22	मणिपुर	147987	412	17	148416
23	मेघालय	53908	393	34	54335
24	मिजोरम	44951	207	6	45164
25	नागालैंड	60701	170	16	60887
26	ओडिशा	2044179	9787	581	2054547
27	पुडुचेरी	94030	654	62	94746
28	पंजाब	1822767	16546	1205	1840518
29	राजस्थान	3735958	26543	1598	3764099
30	सिक्किम	28908	158	13	29079
31	तमिलनाडु	5270701	38540	2735	5311976
32	तेलंगाना	2547334	19604	1749	2568687
33	त्रिपुरा	271441	679	45	272165
34	उत्तर प्रदेश	7062336	39018	2475	7103829
35	उत्तराखंड	539209	3945	270	543424
36	पश्चिम बंगाल	4553732	23323	1706	4578761
	कुल:-	65320665	476982	35721	65833368

